प्रदेश में तेजी से बढ़ेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी 10 लाख की सब्सिडी

लखनऊ। यूपी में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब ईवी चार्जिंग स्टेशनों के इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत पर भी 10 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर सब्सिडी देने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में इस नीति के क्रियान्वयन के लिए इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी है।

इलेक्ट्रिक वाहन ईकोसिस्टम को मजबूत करने और सेवा को मजबूत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों की अपस्ट्रीम अवस्थापना (इंफ्रा) लागत को ईवी सब्सिडी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय प्राधिकृत इलेक्ट्रिक वाहन समिति की बैठक में लिया गया।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 में किए गए इस संशोधन से चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर्स की बड़ी

इंफ्रास्ट्रक्चर लागत पर सब्सिडी देने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी

समस्या दूर हो गई है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत को निवेश में शामिल नहीं करने के कारण निवेशक न्यूनतम 25 लाख की निवेश सीमा पूरी नहीं कर पा रहे थे और सब्सिडी से वंचित रह जाते थे।

नीति के तहत राज्य में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने वाले ऑपरेटरों को आकर्षक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। उन्हें एक बार पूंजी अनुदान दिया जाता है, जिसमें भवन निर्माण, सिविल वर्क्स, चार्जर, अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी उपकरण, यूटिलिटीज, उपकरण और अन्य संबंधित संपत्तियों (जमीन लागत को छोड़कर) पर हुए निवेश की 20% राशि और अधिकतम 10 लाख प्रति इकाई तक सब्सिडी के रूप में दी जाती है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ईवी चार्जिंग स्टेशनों में अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है। ब्यूरो